चौतरफा, क्यों फ़ेल हो रहे हैं मोदी ? जमीनी हकीकत भयावह!

विवेक की विशेष रपट

मन न रंगाये, रंगाये जोगी कपड़ा! यह कहावत यूं तो भारत के सभी धर्मगुरुओं से लेकर राजगुरुओं पर लागू होती है। पर प्रधानमंत्री मोदी इसके प्रबलतम दावेदार हैं।

बिहार के अररिया ज़िले से फ़रीदाबाद आये मोहम्मद आसिफ और उनके कई साथी मज़दूरों की जीवन यात्रा में मोदी सरकार की कई फ्लैगशिप स्कीमों की पोल खुल गई।

मोहम्मद आसिफ़ (62 वर्ष) अररिया ज़िले में दो वर्ष पूर्व आई बाढ में अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं। उनका कच्चा मकान भी बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। उसी वर्ष आसिफ़ से ग्राम प्रधान ने 10,000/- रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लिये परंतु आज तक न ही उन्हें मकान मिला और न सरकार के पास जमा कराने के नाम पर लिए गए 10, हजार रुपये वापिस मिले।

मोहम्मद सज्जाद (25 वर्ष) ने भी अपने ग्राम प्रधान को 8000/-रुपये सूद पर लेकर बतौर जमाराशि दिये। परंतु आज तक उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं मिला, उलटे जमा की हुई धनराशि थी सूद भरने में खर्च हो गई। उल्टे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान पाने की महत्वकांक्षा ने दोनों पर सूद का बोझ ऐसा लादा कि उन्हें गांव छोड़ने पर ही विवश कर दिया।

इरशाद ने बताया कि मनरेगा के नाम पर गांव में काम नहीं मिलता, बस कभी-कभी मुखिया हस्ताक्षर कराते हैं किसी रजिस्टर में और कुछ पैसे देकर चलता करते हैं। बाकी की सब रकम यकीनन ऊपर से लेकर नीचे तक के कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि डकार जाते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा जैसी महत्वकांक्षी योजनाओं का ज़मीनी हश्र वैसा ही प्रतीत होता है जैसा कि इन मज़दूरों का। ऐसे में गांवों से शहरों की ओर पलायन का रुकना असंभव ही है। वहीं शहरों में शोषण के अन्य कई स्वरूपों से इन मज़दूरों को रूबरू होना पड़ता है।

फ़रीदाबाद शहर में पी.एन.जी. पाइप लाईन डालने का काम जोरों शोरों से अडानी ग्रुप को सौंपा गया है। मोदी सरकार का 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का नारा अदानियों, अम्बानियों के लिये कितना ईज़ हुआ उसकी बानगी 'मूडिज़' की प्रकाशित इंडेक्स रिपोर्ट में हम देख चुके हैं। परन्तु इन कम्पनियों के प्रोजेक्ट्स में कार्यरत मज़दूरों की स्थिति बहुत दयनीय है। इरशाद, सज्जाद और आसिफ ठेकेदार अहमद के पास अडानी ग्रुप की पीएनजी पाईपलाइन प्रोजेक्ट में मज़दूर हैं। उन्हें प्रति मीटर गड्ढा खोदने की मज़दूरी 50/- रुपये प्रति मज़दूर दी जाती है जबकि बिचौलिया ठेकेदार कम्पनी से 75-100/- रुपये प्रति मीटर लेता है।

बिचौलिया की मौजूदगी को समाप्त करने का दावा करने वाली मोदी सरकार की लाडली कम्पनियां ही यहां बिचौलियों को पाले रखने में दिलचस्पी रख रही हैं। कम्पनी का सुपरवाइजर जहां एक ओर सांठ-गांठ से अपना ही ठेकेदार नियुक्त करवाने का प्रयास करता हैवहीं दोनों मिलकर मज़दूरों के काम में कोई न कोई कमी निकालकर उनकी तय मज़दूरी का कुछ हिस्स भी डकार लेते हैं। बहस करने पर मज़दूरों के साथ मारपीट का होना आम बात है।

सज्जाद, आसिफ़ रीना, रामदरस, इरशाद सबकी स्थिति कमोबेश एक सी है। इनमें से अधिकतर लोग सेक्टर-7 की पुलिस चौकी के पास कामचलाउ झुग्गियों में रहते हैं। नहाने-धोने का पानी पुलिस चौकी से ले आते हैं परन्तु पानी की कमी के चलते हफ़्ते में एकाध बार ही इन्हें नहाना मयस्सर होता है। पानी उपलब्ध हो तो कार्यस्थल पर ही हाथ-मुंह धो लेते हैं।

स्वच्छ भारत अभियान को नेताओं की नौटंकी बताते हुए मुसया और महानंद नामक दो मज़दूरों ने बताया कि शौच के लिये इस 'स्मार्ट' शहर में उनके पास कोई स्थान नहीं। इसलिये वह सब अंधेरे भोर में ही खुले में शौच को मजबूर हैं। अधेड़ उम्र की रीना पति रामदास के साथ बाईपास की झुग्गियों में रहती हैं।

रीना के पास मोदी की बहुप्रचारित उज्जवला योजना के तहत कोई भी एलपीजी का सिलेंडर नहीं है। इस लिये उनका खाना लकड़ियों पर बनता है। इसी प्रकार अन्य सभी मज़दूर काम से वापिस जाते समय चील सी नज़रें गड़ाए सड़क पर लकड़ियों के टुकड़े बटोरते जाते हैं। इन लकड़ियों पर खाना पकाकर जहां उज्वला योजना को मुखाग्नि दी जाती है वहीं दूसरी ओर पेरिस पर्यावरण समझौते में किये भारत के सभी वायदों को धुएं में उड़ाया जाता है।

प्रकृति के प्रकोप से बच कर जो लोग शहरों में मज़दूरी करने आते हैं वह सरकार की लूट पर आधारित कुव्यवस्था की मार से नहीं बच सकते। प्रधानमंत्री आवास योजना मेंजहां मुखिया के माध्यम से इन गरिबों से पैसे उगाहे जा रहे हैं वहीं अन्य योजनाओं की सुविधायें भी इनके लिये नदारद हैं।

ईज़ ऑफ़ डूईंग के नाम पर कॉरपोरेटों के लिये सुविधायें मुहैया कराने में लगी हमारी तथाकथित गरीब हितैषी मोदी सरकार को असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों के इस शोषण का क्या ज्ञान नहीं? खुले में शौच से मुक्ति का हल्ला करने वाली सरकार को पता होना चाहिये कि मज़दूर अंधेरे में शौच को क्यों मज़बूर हैं?

श्रमिकों के दम पर खड़े अडाणी ग्रुप सरीखे कॉरपोरेट की क्या इनको रहने की एक व्यवस्थित सुविधा, पीने का पानी तथा साथ ही टेम्परेरी शौचालय मुहैया कराने की शर्तें टेंडर में नहीं डाली जा सकती और क्या इन शर्तों को ज़मीनी तौर पर लागू नहीं कराया जा सकता?

फ़िलहाल तो हकीकत यह है कि मोदी सरकार की तमाम फलैगशिप योजनाओं की पहुंच उन लोगों तक नहीं है जिनके नाम पर अमिताभ बच्चन करोड़ों रुपये लेकर ब्रांड अम्बेसडर बन जाते हैं और उन्हीं का मजाक बनाकर पूरे श्रमिक एवं हाशिए पर बैठे कमज़ोर वर्ग को स्वच्छ भारत अभियान का पाठ पढ़ाते हैं।

सत्तारुढ़ होते ही नाम बदल-बदल कर कई फ्लैगशिप स्कीमो की बम्बारमेंट करने वाली मोदी सरकार का किसी भी योजना की वास्तविकता के आधार पर प्रोगेस कार्ड तैयार किया जाए तो मोदी जी धक्का मारकर पास नहीं हो सकते। इसलिये मोदी जी आम आदमी की नज़र में आप फेल हैं।

बिल्डिंग एन्ड अदर कन्सट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट 1956 के तहत खर्च

1. मज़दूरों की सुरक्षा पर
2. स्वास्थ्य सुविधाओं पर
3. कल्याणकारी योजनाओं पर

इस एक्ट के तहत सभी राज्यों के स्टेट बिल्डिंग एवं कन्स्ट्रक्शन बर्कर वेलफ़ेयर बोर्ड का गठन करना आवश्यक होगा जिसमें:-

1. दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान करना
2. 60 वर्ष से अधिक की आयु पर पेंशन सुविधा
3. घर बनाने के लिये लोन मुहैया कराना जैसे प्रावधान शामिल हैं।

आसाराम का बाप झांसाराम!

1, मई 2016 को बलिया की धरती को नमन करते हुये प्रधानमंत्री मोदी को स्वर आज भी कानों में गूंजते हैं। मोदी जी ने मज़दूर दिवस पर स्वयं को देश का 'मज़दूर नम्बर एक' बताते हुए सभी मज़दूरों को कोटि-कोटि प्रणाम एवं अभिनंदन किया।

इस अवसर पर मोदी ने कहा कि मज़दूरों के पसीने में वो ताकत है कि दुनिया को एक साथ जोड़े रखें। यह भी कि मज़दूरों की पेंशन 1000/-रुपये करने जा रहे हैं।

अदानी गैस के बंधुआ मज़दूर मोहम्मद आसिफ़ जिनकी उम्र 62 वर्ष है उनको आज तक ऐसी किसी पेंशन की जानकारी नहीं है, न ही कोई राशि इस रूप में उन्हें कभी प्राप्त हुई है।

मोदी ने निर्माण कार्य में लगे मज़दूरों को इंश्योरेंस एवं बैंक अकाउंट सुविधाओं की लॉलीपाप देने की भी घोषणा के साथ पेंशन पर व्यापक योजना बनाने का आश्वासन दिया था। इन वायदों पर कितना काम हुआ ये स्वयं मोदी जी ही जानते हैं।

जिन लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी उन 10 लाख लोगों के लिये तालियां तो पिटवाई गई परंतु रीमा एवं इन अन्य मज़दूरों जैसे करोड़ों महिला मज़दूरों को इसका लाभ नहीं मिला। बेशक, आंकड़ा कागजों की शोभा बढ़ा रहा है, बस।

मोदीजी यहीं नहीं रुके। अपने बड़बोलेपन की आदतानुसार उन्होंने कहा ''अब मेरे हाथ में साधन है। मैं गरीबी को परास्त कर के रहूंगा। सबको शिक्षा, रोजगार, आवास, शौचालय, पीने का पानी मुहैया कराकर गरीबी का नामोनिशान मिटा दूंगा।''

इतना सब एक ही भाजपा में कहने का जीवट मोदी जी में ही हो सकता है। सुनने का जीवन तो जनता में कई वर्षों से है। अन्यथा मज़दूर जानते हैं कि यह सभी सुविधायें मात्र चुनावी शगूफ़ा हैं जो भाषण के साथ ही फ़ाख्ता हो जायेंगे और हो गये। अब फ़िर 1 मई मज़दूर दिवस आ गया है। देखें किन नई घोषणाओं के साथ मोदी जी गरीबी को परास्त कर देंगे फ़िर से।

-बिबेक

दुनिया में सर्वाधिक बेरोज़गारों वाला देश बना भारत

रोज़गार लगातार घट रहा है और स्व-रोज़गार के अवसर कम हो रहे हैं

सत्यप्रकाश

लेबर ब्यूरो के हाल में जारी आँकड़ों ने मोदी सरकार के लम्बे-चौड़े दावों की पोल खोल दी है और उस सच्चाई को आँकड़ों की शक्ल में हमारे सामने रख दिया है जिसे आम लोग अपने अनुभवों से लगातार महसूस कर रहे हैं। भारत को दुनिया में सबसे अधिक बेरोज़गारों वाला देश होने का गौरव हासिल हो गया है। समावेशी विकास सूचकांक में दुनिया में भारत साठवें स्थान पर पहुँच गया है, यानी अपने पड़ोसियों से भी काफ़ी नीचे।

आँकड़े बताते हैं कि देश में रोज़गार लगातार घट रहा है और स्व-रोज़गार के अवसर कम हो रहे हैं। सामाजिक-आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी के साथ देश में हो रहे ''विकास'' का दूसरा पहले यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बताया जा रहा है। 'बिज़नेस एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स' यानी व्यवसाय करने में सुविधाओं आदि के मामले में हम 30 सीढ़ी ऊपर चढ़ गये हैं।

सच यही है कि जैसे-जैसे देश में विकास हो रहा है, वैसे-वैसे यहाँ असमानता आसमान छूती जा रही है। अमीरों और ग़रीबों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। आज़ादी के बाद से ही देश के नये सत्ताधारियों ने विकास का जो रास्ता चुना था, उस पर चलते हुए इसी दिशा में समाज आगे बढ़ रहा था। लेकिन पिछले तीन दशकों से जारी निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों ने इस रफ़्तार को बहुत तेज़ कर दिया है। देश के सारे संसाधन मुट्ठीभर लोगों के हाथों में सिमटते जा रहे हैं। इस दौर में देश में दौलत के पैदा होने की रफ़्तार बहुत तेज़ रही है। बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएँ कम्पनी, क्रेडिट सुइस ग्लोबल के अनुसार, वर्ष 2000 से, भारत में मौजूद सम्पदा के कुल मूल्य में हर साल 9.9 प्रतिशत की दर से बढ़ोत्तरी हो रही है, जबकि दुनिया के पैमाने पर यह औसतन सिर्फ़ 6 प्रतिशत रहा है। लेकिन जिन लोगों की मेहनत के बल पर यह सम्पदा पैदा हो रही है, वे इससे पूरी तरह वंचित हैं।

समाचार एजेंसी ए.एन.आई. की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सार्वजनिक संसाधनों के वितरण में असमानता बहुत बढ़ गयी है और आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा अब भी ग़रीबी रेखा के नीचे जीता है। हालत यह है कि 2017 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत खिसक कर 100वें पर पहुँच गया है (2016 में हम 97वें स्थान पर थे)। बंगलादेश, श्रीलंका, म्यांमार और कई अफ्रीकी देश भी इस मामले में भारत से बेहतर स्थिति में हैं।

'ऑक्सफ़ेम' की रिपोर्ट 'बढ़ता अंतर-भारत असमानता रिपोर्ट 2018' के मुताबिक, दुनिया के पैमाने पर सिर्फ़ एक प्रतिशत लोगों के हाथों में दुनिया की कुल दौलत का 50 प्रतिशत है। भारत में एक प्रतिशत लोगों के हाथों में देश की 58 प्रतिशत सम्पत्ति है (कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह और भी ज़्यादा है), और केवल 57 अरबपतियों के पास इतनी दौलत है जो देश की 70 प्रतिशत आबादी की कुल सम्पत्ति के बराबर है।

भारत आबादी के लिहाज़ से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देश की 65 प्रतिशत आबादी की औसत उम्र 35 साल से कम है। किसी भी समाज के लिए इतनी बड़ी युवा आबादी एक बहुत बड़ी ताक़त होती। लेकिन भारत में इस आबादी का बड़ा हिस्सा बेरोज़गार है। आर्थिक सहकार और विकास संगठन के आँकड़ों के अनुसार, देश में रोज़गार से वंचित युवाओं की संख्या बहुत अधिक है जिसके कारण समाज में असन्तोष बढ़ रहा है।

इसी तरह, देश की कुल कामगार आबादी में स्त्रियों की भागीदारी अभी केवल 27 प्रतिशत है। (कामगार आबादी में घरेलू काम और देखभाल जैसे कामों को नहीं जोड़ा जाता जिनके लिए कोई भुगतान नहीं होता।) विश्व बैंक के अनुमान बताते हैं कि 2004-05 से लेकर 2011-12 के बीच 19.6 प्रतिशत स्त्रियाँ कामगार आबादी से बाहर निकल गयीं, जोकि बहुत बड़ी संख्या है। हालाँकि, ये आँकड़े पूरी तस्वीर नहीं बताते क्योंकि स्त्रियों की एक अच्छी-खासी आबादी घरों पर रहकर बेहद काम दामों पर पीसरेट आदि पर किये जाने वाले कामों से जुड़ी है जो अक्सर ऐसी गणनाओं से बाहर ही रह जाती है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि अगर भारत में कामगार स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर हो जाये तो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो जायेगी। ऐसे हवाई अनुमानों पर हँसा ही जा सकता है क्योंकि जब पहले से मौजूद कामगार आबादी के ही बड़े हिस्से को काम नहीं मिल रहा है तो स्त्रियों की इस विशाल आबादी के लिए रोज़गार कहाँ से आयेगा। लेकिन सरकार और देशी-विदेशी पूँजीपतियों की संस्थाएँ औरतों को काम में लगाने के लिए तरह-तरह की योजनाएँ इसलिए बना रही हैं क्योंकि उनसे कम मज़दूरी पर ज़्यादा काम कराये जा सकते हैं। वे यह भी सोचते हैं कि स्त्रियों को ग़ुलाम बनाकर रहना भी ज़्यादा आसान होगा।

पिछले कुछ सालों से स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी तरह-तरह की योजनाएँ बनायी गयी हैं, लेकिन इन योजनाओं के दफ़्तर और प्रचार सँभालने वाले लोगों को रोज़गार देने के अलावा देश में बेरोज़गारी कम करने की दिशा में इससे कोई प्रगति नहीं हुई है। ज़्यादातर योजनाएँ तो चुनावी घोषणाओं की तरह बिना किसी तैयारी के शुरू कर दी गयी हैं। उद्योगों की ज़रूरतों और युवाओं को सिखाए जा रहे कौशलों में कोई तालमेल ही नहीं है और अधिकांश मामलों में दी जा रही ट्रेनिंग इतनी घटिया है कि उससे कोई रोज़गार नहीं मिल सकता।

वैश्विक मन्दी, नोटबन्दी और जीएसटी की मार

जिन उद्योगों में सबसे अधिक रोज़गार मिलता था, उनकी हालत पतली है। 'लाइव मिंट' अखबार के अनुसार न केवल इन कम्पनियों के निर्यात की हालत खस्ता है बल्कि औद्योगिक उत्पादन के आँकड़े भी बताते हैं कि इन सेक्टरों में वृद्धि बहुत सुस्त है। इतना ही नहीं, श्रम-सघन उत्पादों का आयात बढ़ रहा है। इन सबके चलते रोज़गार की हालत और भी बदतर होने वाली है।

भारत के श्रम-सघन उद्योगों, जैसे टेक्सटाइल, आभूषण और हीरे-जवाहरात, चमड़ा आदि का निर्यात घट रहा है। पिछले साल जुलाई में जीएसटी लागू होने के बाद से इसमें गिरावट तेज़ी से जारी है। इससे पहले नोटबन्दी के दौरान सूरत के आभूषण उद्योग से हज़ारों मज़दूरों सहित देश में लाखों मज़दूरों का काम छूट गया था जिनमें से बहुत से अब भी खाली बैठे हैं। चमड़ा, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प, खेलकूद के सामान, फर्नीचर और मैन्युफैक्चरिंग के अन्य सामानों के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में पिछले वर्ष अप्रैल से तेज़ी से गिरावट आयी है। जिन सेक्टरों में श्रम-सघनता कम है, यानी जहाँ रोज़गार भी कम पैदा होता है, वे अब थोड़ा उबरे हैं।

रिपोर्ट कहती है कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे महारथियों के कारनामों के बाद आभूषण और जवाहरात उद्योग के लिए बैंकों से कर्ज़ मिलने में कठिनाई होगी जिसका भी सीधा असर रोज़गार पर पड़ेगा।

टेक्सटाइल उद्योग में पड़ोसी देशों बंगलादेश और वियतनाम के साथ तीखी प्रतिस्पर्धा है। नेपाल भी अपनी सस्ती श्रमशक्ति टेक्सटाइल कम्पनियों की सेवा में लगाने के लिए तेज़ी से एसईज़ेड आदि बनाने में लगा है। इस कारण इस क्षेत्र में निकट भविष्य में रोज़गार बढ़ने की सम्भावना कम ही लग रही है। भारत से निर्यात होने वाले टेक्सटाइल में सबसे बड़ा हिस्सा धागे, तौलियों और सिले-सिलाए कपड़ों का है। पिछले करीब पूरे साल भारत से धागे का निर्यात घटा है। जून 2017 से संयुक्त अरब अमीरात को होने वाले निर्यात में 45 प्रतिशत की गिरावट के कारण सिले-सिलाए कपड़ों के निर्यात की हालत खराब रही है। ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी और यूरोपीय संघ-वियतनाम मुक्त व्यापार समझौते के बाद वियतनाम की इस बाज़ार में हिस्सेदारी और बढ़ेगी जिसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। भारत के निर्यातों के एक बड़े खरीदार अमेरिका में बढ़ते संरक्षणवाद के कारण भी भारत के निर्यातकों की मायूसी बढ़ सकती है। मोदी भक्त चाहे जितनी डोनाल्ड ट्रम्प की भक्ति कर लें, सच यही है कि ट्रम्प संकट से जूझती अमेरिकी अर्थव्यवस्था का हित देखेगा न कि भारत के पूँजीपतियों का।

कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाले सेक्टरों की हालत में सुधार जल्दी होता नहीं दिख रहा है। निर्माण उद्योग भी ऐसी ही हालत से गुज़र रहा है। देशभर में लाखों फ्लैट खाली पड़े हैं और निर्माण गतिविधियों में भारी सुस्ती बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार उत्पाद और निर्यात में कमज़ोरी का असर समग्र उपभोग पर भी पड़ेगा जिसके असर से सेवा उद्योग में भी सुस्ती आ सकती है। ग्रामीण अर्थव्यस्था पर इसके नतीजे दिखने भी शुरू हो गये हैं।

देश पर राज कर रहे जुमला-नरेशों की बातों पर मत जाइये। कौवा कान ले गया की तर्ज़ पर कोई किसी के खिलाफ़ आपको भड़का दे तो आँखों पर पट्टी बाँधकर आग में कूदने मत लगिये। देश-समाज और अपनी ज़िन्दगी की असली तस्वीर को पहचानिये और असली सवालों पर लड़ने की तैयारी करिये। वरना कल तक बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं!